

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 653
3 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: खाद्य तेल सुरक्षा

653. श्री सुखदेव भगत:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या घरेलू तिलहन की कम कीमतों के कारण किसान तेजी से तिलहन से मक्का की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या तेल आत्मनिर्भरता के सरकारी लक्ष्य के बावजूद, 30 जून, 2025 की मंत्रालय रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है; और
- (ग) इस प्रवृत्ति को पलटने और खाद्य तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल नीतिगत अंतःक्षेप (जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी या आयात शुल्क) कार्यान्वित किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएंडएफडब्ल्यू) के अंतिम अनुमान के अनुसार, तिलहन की खेती का रकबा वर्ष 2023-24 में 301.92 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 304.40 लाख हेक्टेयर हो गया है। तिलहन का उत्पादन भी वर्ष 2023-24 में 396.69 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 429.89 लाख टन हो गया है।

घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की ओर बढ़ने के लिए 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दी गई थी। किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने, बाजार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा करने, आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और आयात शुल्क लागू किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत खरीद में तिलहन भी शामिल हैं और इससे किसानों को बेहतर मूल्य और आय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है।
